के संबंध में 1990 में गठित कार्यदल की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा देश में भूमि सुधार एवं भवन-निर्माण सामग्री से संबंधित क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां उड़न राख के समुपयोजन की संभावना है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उड़न राख समुपयोजन को प्रोत्साहित किए जाने संबंधी कार्य के लिए शहरी विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन बिल्डिंग मैटीरिल्स एण्ड टैक्नोलाजी प्रमोशन काउंसिल को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उड़न राख आधारित भवन-निर्माण सामग्री के निर्माताओं के लिए वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 के दौरान उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क में छूट दी गई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु "फ्ले फ्लाई ऐश ब्रिक" के संबंध में विशिष्टियां तैयार की गई हैं। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय भवन-निर्माण नीति (नेशनल हाउसिंग पालिसी) में भी उड़न राख पर आधारित कम लागत वाली भवन-निर्माण सामग्री के उपभोग पर काफी बल दिया गया है। केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा भी उड़न राख पर आधारित प्रोटो-टाइप टाइल का विकास किया गया है। सरकार को आशा है कि ऊपर उल्लिखित उपायों के फलस्वरूप, देश में उड़न राख समुपयोजन संबंधी स्थिति में सुधार होगा।

U. S. Investment in India's Power Sector

2057. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of POWER be pleased to refer to Unstarred Question 1270 given in the Rajya Sabha on 21st July, 1992 and state:

(a) whether U.S. companies which have shown, interest in investing in India's power sector have put forward any terms and conditions for investing in power generation in the country?

(b) if so, what are the details herof; and

(c) what is the reaction of Government to such proposals and their terms and conditions?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) A number of US Companies have shown interest in investing in India's power sector.

(b) and (c) They have been advised to finalise the detailed terms and conditions with the concerned state Governments/State Electricity Boards.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications of the Ministry of Communications (Department of Telecommunication)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAJESH PILOT): Madam, I lay on the Table, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Communications (Department of Telecommunication):—

(i) G.S.R. No. 543(E), dated the 21st May, 1992, publishing the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 1992.

(ii) G.S.R. No. 587(E), dated the 10th June, 1992, publishing the Indian Telegraph (Third Amendment) Rules, 1992. [Placed in Library. *See* No. LT-2305/92]

Report of the Comptroller and Auditor General of India in respect of Hindustan Latex Limited

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARADEVI SIDDHARTHA): Madam, I lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy (in English and Hindi) of the Report of the Comptroller and Auditor General of India—Union Government [No.